

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

GCMS NO 2017/00150

अपील संख्या - 114/17

1. रामफूल ठण्डी
2. अकलू
3. मूडिया
4. करौली

पिसरान रंगलाल जातियान मीना निवासीयान कांचरोदा तहसील सपोटरा जिला

अपीलांट

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र गजबी
 2. ब्रम्हमसिंह पुत्र महेन्द्र
 3. रूकम पुत्र महेन्द्र जातियान मीना निवासीयान कांचरोदा तहसील सपोटरा जिला करौली
- रेसपो

अपील विरुद्ध मु0नं0 61/08 निर्णय व डिक्री दिनांक 1.11.17 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सपोटरा जिला करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री नेमीचंद गर्ग
अभिभाषक रेसपो0 की और से कोई उपस्थित नहीं

दिनांक 02.06.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 1.11.17 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सपोटरा पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांटगण ने दाव बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व दखल इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा न0 661 रकबा 12 विस्वा वाके ग्राम कांचरोदा तहसील सपोटरा जो कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काशत की आराजी है, जिससे दीगर किसी का कोई संबंध नहीं है। जिसको वादीगण ही काशत करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण सहजोर एवं लडाकू व्यक्ति है। जिन्होंने ताकत के बल पर दिनांक 13.7.08 को उक्त आराजी में गोबर व ईधन डालना शुरू कर दिया है। प्रतिवादीगण वादीगण को काशत करने में अवरोध पैदा करते हैं। दिनांक 13.7.08 को जब वादीगण ने प्रतिवादीगण से गोबर व ईधन डालने की मना किया तो प्रतिवादीगण वादीगण को मारने पर आमामदा हो गये। इसलिए प्रतिवादीगण को उक्त आराजी से बेदखल कर जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः वादीगण का दावा डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को आराजी खसरा न0 661 रकबा 12 विस्वा वाके ग्राम कांचरोदा तहसील सपोटरा से बेदखल किया

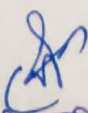
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण की उक्त आराजीयात में काश्त करने में किसी प्रकार की मदालखत नहीं करे ना ही किसी दीगर से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/अपीलांटगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पों को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पों बाबजूद तामिल उपस्थित नहीं होने से बहस अपीलांट अभिभाषक की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादीगण को रिकार्ड खतेदार काश्तकार मानते हुए भी दखल का दावा खारिज कर कानूनी भूल की है। प्रतिवादीगण/रेस्पों का कोई साधिकार एडवर्स पजेशन कब्जा न होते हुए भी अदालत मातहत ने दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है। दखल एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दवा होने पर भी अदालत मातहत ने दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है। अपीलांट की कोई सहमति न होते हुए भी सहमति से कब्जा मानने में अदालत मातहत ने भूल की है। अदालत मातहत ने तनकी न० 1 आंशिक रूप से स्वीकार करने में भूल की है। अदालत मातहत ने तनकी संख्या 2, 3, 4 अपीलांट के विरुद्ध तय करने में कानूनी भूल की है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट गलत बनाई है। पटवारी की रिपोर्ट को न्यायालय में साबित भी नहीं कराया है ना ही वादी को जिरह का अवसर मिला है। दिनांक 1.11.17 की मौका रिपोर्ट है जो ग्राम कांचरोदा तैयार की है जिस पर पक्षकारों को बिना सूचना बिना हस्ताक्षर कराये तैयार की है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है तथा निर्णय दिनांक 1.11.17 का है जिसके बाबत सुनवाई का अवसर अपीलांट को नहीं दिया गया है ना ही दिनांक 1.11.17 को मौका रिपोर्ट पत्रावली पर थी। गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट्स न होते हुए भी उस पर विश्वास करने में अदालत मातहत ने भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाकर दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर आराजी खसरा न० 661 रकबा 12 विस्वा वाके ग्राम कांचरोदा तहसील सपोटरा से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण/अपीलांट को दिलाया जावे तथा रेस्पों/प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अपीलांट/वादीगण की उक्त आराजीयात में काश्त करने में किसी प्रकार की मदालखत नहीं करे ना ही किसी दीगर से करावे।

अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात खसरा न० 661 रकबा 12 विस्वा ग्राम कांचरोदा तहसील सपोटरा की खातेदारी वादी/अपीलांट के नाम दर्ज है। अपीलांट/वादीगण द्वारा विवादित आराजीयात के कब्जे काश्त में उपरोध प्रतिवादीगण द्वारा किये


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जाने का वाद कारण का अंकन करते हुए प्रतिवादीगण/रेस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की इस्तदुआ चाही गई थी। पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट में विवादित आराजीयात आबादी के काम आ रही है जिससे स्पष्ट है कि भूमि पर किसी प्रकार की कोई काश्त नहीं की जाती है। इस प्रकार अपीलान्ट का यह कथन मनगढन्त है। जब काश्त ही नहीं होती है तो रेस्पो/प्रतिवादीगण द्वारा किस प्रकार काश्त में मदालखत किया जाता है। अपीलान्ट/वादीगण का वाद पत्र में कथन रहा कि प्रतिवादीगण/रेस्पो0 उक्त आराजीयात में पशु बाड़ा बनाकर रहवास कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात में काश्त नहीं होती है। वादीगण/अपीलान्ट का विवादित आराजीयात कर कब्जा ही सिद्ध नहीं होता है। विवादित आराजीयात पर अपीलान्ट/वादीगण की सहमति से ही प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा पशुओं के लिए बाड़ा एवं रिहायशी मकान बनाया गया है। अपीलान्ट का यह कथन भी साबित नहीं है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसको सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अपीलान्ट की ओर से ही प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई। वादीगण/अपीलान्टगण के जिम्मे कायम की गई तनकीयात को अपीलान्ट साबित करने में असफल रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलान्ट निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के प्रकरण संख्या 61/08 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.11.17 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजशही अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर